शनिवार , 31 अक्टूबर 2026, ठाणे, मुंबई

दैनिक सिटी न्यूज मुंबई

सच का जोश

वर्ष - 15 • अंक - 66 CITY NEWS MUMBAI

दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट बचाओ

देश बचाओ रैली 1 नवंबर को, महाराष्ट्र से जाएंगे 5,000 कांग्रेस कार्यकर्ता

इंडिया गठबंधन 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली करेगा। राहुल गांधी की पहल पर महाराष्ट्र से 5,000 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। इंडिया आघाडी 1 नवंबर को दिल्ली में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली करेगी। महाराष्ट्र से 5 हजार से अधिक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया और एसआईआर के तहत नाम कटने को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस रैली में राज्य से करीब पांच हजार से अधिक कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। INDIA गठबंधन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का मुद्दा उठाएगा विपक्ष कांग्रेस के मुताबिक, रैली का उद्देश्य देश में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और नागरिकों के मतदान के अधिकार का मुद्दा उठाना है। पार्टी का आरोप है कि



केंद्र की भाजपा सरकार चुनाव आयोग की मदद से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कहना है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए विपक्षी दलों का एकजुट होना जरूरी है। चु महाराष्ट्र से बड़ी भागीदारी की तैयारी महाराष्ट्र कांग्रेस के अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों से नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। पार्टी इसे केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मतदान के अधिकार और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा अभियान बता रही है। दिल्ली में होने वाली इस रैली के जरिए INDIA गठबंधन चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अपने सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में है। नाव आयोग पर कांग्रेस ने लगाए आरोप कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर केंद्र सरकार के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर देशभर की मतदाता सूचियों से करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस प्रक्रिया से मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आंकड़े और उनके कारणों को लेकर भाजपा तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक मतभेद हैं। भाजपा की ओर से पहले कहा गया है कि हटाए गए नामों में बड़ी संख्या मृत मतदाताओं की भी है।

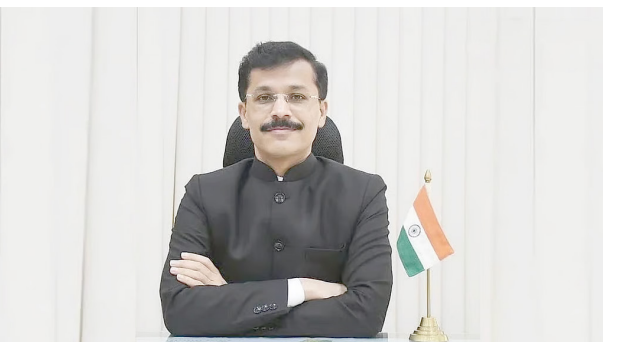
फिर एक होंगी दोनों शिवसेना? शिंदे गुट के विधायक हेमंत पाटिल के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली

शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हेमंत पाटिल के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। जानिए क्या दोनों शिवसेनाएं फिर एक होंगी और है इस बयान के मायने। हेमंत पाटिल के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। दोनों शिवसेनाओं के एकजुट होने पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निर्णय लेंगे। जमीनी स्तर के शिवसैनिक आज भी एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर दोनों शिवसेना के दोनो धड़ों के एक साथ आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट के विधान परिषद सदस्य एवं विधायक हेमंत पाटिल के एक ताजा बयान ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है हेमंत पाटिल ने राजनीति के अनिश्चित स्वभाव पर



बात करते हुए कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने टिप्पणी की कि जिनके खिलाफ जिंदगी भर हथियार उठाए, आज उन्हीं के साथ बैठने का वक्त आ चुका है। दोनों शिवसेनाओं के एकजुट होने के फैसले पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में एकनाथ शिंदे जो भी योग्य फैसला लेंगे, वह फैसला पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मान्य होगा। शिवसैनिकों का आपसी प्यार और नांदेड का जिक्र हेमंत पाटिल ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले शिवसैनिकों के आपसी संबंधों का जिक्र करते हुए एक अहम बात रखी। उन्होंने कहा कि भले ही एक शिवसेना के दो हिस्से हो चुके हैं और दो अलग-अलग शिवसेनाएं बन गई हैं, लेकिन आम शिवसैनिकों के बीच एक-दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव आज भी वैसा ही बना हुआ है। शिवसैनिक आज भी एक-दूसरे के सुख-दुख में बढ़-चढ़कर शामिल होते हैं और साथ आते हैं। पाटिल ने कहा कि यदि शिवसेना अंदर से एक होती, तो आज पूरे महाराष्ट्र में एक अलग ही राजनीतिक परिदृश्य दिखाई देता। उन्होंने नांदेड जिले की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज नांदेड जिले में पार्टी और कार्यकर्ताओं को जिस संघर्ष और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वह नौबत कभी नहीं आती। भाजपा से मतभेद और पालकमंत्री को सलाह बयान के दौरान हेमंत पाटिल ने सत्ताधारी गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के रिश्तों पर भी अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि स्थानीय स्तर पर भाजपा और शिवसेना के बीच निश्चित रूप से मतभेद मौजूद हैं। इन मतभेदों को दूर ...शेष 7 पर

FDA की बड़ी कार्रवाई, 5.01 करोड़ का एक्सपायरी सामान और 18.95 करोड़ का मिलावटी तेल जब्त, 80 लाइसेंस निलंबित



महाराष्ट्र एफडीए ने छापे मार 5.01 करोड़ का एक्सपायरी सामान व 18.95 करोड़ का मिलावटी तेल जब्त किया। नवी मुंबई के तुर्भे में 4.12 करोड़ का माल बरामद, नियम कड़े। एफडीए ने 5.01 करोड़ का एक्सपायरी खाद्य सामान जब्त किया। तेल मिलावट के मामलों में 18.95 करोड़ का माल पकड़ा गया। कार्रवाई में 34 आरोपियों पर कार्रवाई और 87 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। महाराष्ट्र के अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) ने एक्सपायरी खाद्य सामानों की दोबारा बिक्री और तेल में मिलावट के खिलाफ एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। जून से अक्टूबर 2026 के बीच हुई छापामार कार्रवाई के दौरान कुल 5.01 करोड़ रुपये का एक्सपायरी सामान जब्त किया गया है, जबकि तेल मिलावट के मामलों ...शेष 7 पर

शिंदे के साथ खिलवाड़ शुरू, वडेट्टीवार बोले- पीछा छुड़ाने पर तुली केसरिया पार्टी



विधान परिषद नतीजों के बाद महायुति में तनाव बढ़ा। वडेट्टीवार ने दावा किया कि बीजेपी शिंदे से पीछा छुड़ा रही है, वहीं राज-उद्धव से फडणवीस की मुलाकात के बाद शिंदे गुट सतर्क। विधान परिषद चुनाव के बाद बीजेपी और शिंदे गुट में तनाव बढ़ने के आरोप। विजय वडेट्टीवार ने शिंदे को निशाना बनाने और फंड की फाइलें रोकने का दावा किया। शिंदे ने नेताओं को बयानबाजी से बचने और विवाद सुलझाने के लिए बातचीत के निर्देश दिए। धान परिषद के ...शेष 7 पर

म्हाडा के ठेकेदारों को मिलेगी राहत

15 दिन में बिलों की जांच और 5 दिन में भुगतान करना होगा अनिवार्य

म्हाडा ने ठेकेदारों के बिल भुगतान में देरी रोकने को नए निर्देश जारी किए। बिल जमा होने पर 15 दिनों में जांच और 5 दिनों में भुगतान अनिवार्य, देरी पर होगी सीधी कार्रवाई। म्हाडा ने ठेकेदारों के बिलों के भुगतान में देरी रोकने के लिए नए आदेश जारी किए। कार्यकारी अभियंता को 15 दिनों में बिल की जांच और लेखाधिकारी को 5 दिनों में भुगतान करना होगा। बिना ठोस कारण देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। म्हाडा प्राधिकरण के तहत निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों को अब अपने बिलों के भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिलों को बिना वजह



लंबित रखने और निर्माण कार्यों में देरी रोकने के लिए म्हाडा ने नई समयसीमा तय करते हुए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत ठेकेदारों के बिलों की जांच और भुगतान की प्रक्रिया अधिकतम 20 दिनों में पूरी करनी होगी। 15 दिनों में बिलों की जांच अनिवार्य मुंबई म्हाडा और उसके विभिन्न मंडलों में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों के साथ कार्यकारी अभियंता स्तर पर समझौते किए जाते हैं। काम की प्रगति के अनुसार ठेकेदार बिल जमा करते हैं, लेकिन कई बार भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी समस्या को देखते हुए नए आदेश में संबंधित कार्यकारी अभियंता को बिल जमा होने के बाद अधिकतम 15 दिनों के भीतर उसकी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। जांच के बाद बिल को संबंधित मंडल के मुख्य लेखाधिकारी या लेखाधिकारी कार्यालय में भेजना अनिवार्य होगा। अगले 5 दिनों में करना होगा भुगतान नए नियमों के अनुसार, मुख्य लेखाधिकारी या लेखाधिकारी को बिल की वित्तीय जांच पूरी ...शेष 7 पर

PM नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को किया बर्थडे विश, पिता रामविलास पासवान को याद कर हुए भावुक

चिराग पासवान के जन्मदिन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने बधाई दी। इस मौके पर चिराग अपने पिता रामविलास पासवान को याद कर भावुक हो गए और बिहार फर्स्ट का संकल्प दोहराया। पीएम नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को जन्मदिन की बधाई दी। चिराग पासवान ने पिता रामविलास पासवान को याद किया। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आज, 31 अक्टूबर को जन्मदिन है। वे अपना 44वां जन्मदिन मना रहे है। इस अवसर पर देशभर से उन्हें बधाई मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य नेताओं ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चिराग फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में बहुत मददगार साबित होगा। पीएम मोदी ने किया बर्थडे विश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, "केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान को जन्मदिन की बधाई। वे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जो 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने में अहम भूमिका निभाएगा और इससे हमारे किसानों को भी लाभ होगा। मैं





उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।" हेलीकॉप्टर के आकार का केक काटा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने जन्मदिन पर भावुक नजर आए। वे अपनी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर के आकार का केक काटा। इस खास मौके पर, उन्होंने पटना के खगौल स्थित महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। चिराग ने पिता रामविलास पासवान को किया याद मीडिया से बात करते हुए, चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को याद किया और कहा कि आज वे जो कुछ भी हैं, अपने पिता की बदौलत ही हैं। अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि जीवन के इस पड़ाव पर उनकी कमी और भी ज्यादा महसूस होती है। बचपन में अपने पिता के साथ जन्मदिन मनाने की यादें हर साल और भी गहरी होती जाती हैं। चिराग ने जन्मदिन पर हेलीकॉप्टर के आकार का केक काटा और 44वां जन्मदिन मनाया। चिराग ने मां और परिवार का जताया आभार अपनी मां, परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताते हुए चिराग ने कहा कि मुश्किल समय में उनकी मां एक मजबूत सहारा बनकर उनके साथ खड़ी रहीं। उन्होंने पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की भी सराहना की। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने एक पत्र के माध्यम से पार्टी में उनके नेतृत्व और कैबिनेट में उनके समर्पित कार्यों की सराहना की, साथ ही उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया।

तमिलनाडु की जेल में सुरक्षा में कोताही पर एक्शन! उप जेल अधीक्षक पर गिरी गाज, कईयों का ट्रांसफर हुआ

तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने थेनी जिला जेल से 17 कैदियों के फरार होने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जेल उप अधिकारी एन. नागेश्वरन को निलंबित कर दिया गया है। तमिलनाडु जेल की सुरक्षा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई थेनी जेल के उप जेल अधीक्षक को सस्पेंड किया गया 17 कैदियों के भागने की घटना के बाद कार्रवाई हुई तमिलनाडु के जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले में मुख्यमंत्री विजय ने शनिवार को कार्रवाई की है। थेनी जिला जेल के उप जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया और साथ ही जेल कर्मचारियों के बड़े तबादलों का आदेश भी दिया, यह घटना वहां से 17 कैदियों के भागने की घटना के कुछ दिनों बाद हुई है। एएनआई समाचार एजेंसी के अनुसार, अगस्त



2024 से थेनी में कार्यरत उप जेल अधीक्षक एन रामलिंगम को जेल प्रशासन और सुरक्षा निगरानी में विफलता के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर, 17 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी जेलों में सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश विजय ने तमिलनाडु की सभी जेलों में पुख्ता सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। गुरुवार को समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि फरार हुए 17 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया है और अधिकारियों ने उन्हें राज्य भर की उच्च सुरक्षा वाली जेलों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच, चेन्नई के पास पुझल स्थित उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद दो कैदी भी 20 अक्टूबर को फरार हो गए। सात पुलिस टीमों द्वारा दो दिनों की तलाशी के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। हालांकि, एक सप्ताह के भीतर हुई इन दो जेल भंग की घटनाओं के बाद तमिलनाडु सरकार को कार्रवाई करना पड़ा। धोखा देकर भागा था कैदी राज्य सरकार ने गुरुवार को जेल और सुधार सेवाओं के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) डॉ. संदीप राय राठौर का तबादला कर दिया। सोमवार रात को थेनी जिला जेल के 17 कैदियों ने फर्जी चिकित्सा आपातकाल का नाटक किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनमें से एक को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। पीटीआई के अनुसार, जब एक गार्ड ने मदद के लिए उनकी कोठरी खोली, तो कैदियों ने उसे काबू में कर लिया और उस पर हमला किया।

AAP की पहली लिस्ट जारी, 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित; भगवंत मान धूरी से लड़ेंगे चुनाव



AAP ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की।

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी ने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान धूरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। AAP ने शनिवार को 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए बैठक की। इस बैठक में आम आदमी पार्टी 2027 के पंजाब चुनावों के लिए अपने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्य प्रभारी मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। साथ ही चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री भगवंत मान धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को दिया टिकट आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता द्वारा जारी इस घोषणापत्र पर 31 अक्टूबर की तारीख है। पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों के साथ-साथ उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्रों और निर्वाचन क्षेत्र के नंबरों का भी उल्लेख किया है।

दिवाली के पीक सीजन में व्यापारियों का फूटा गुस्सा अब दिल्ली चलो मार्च में जुटेंगे अखिलेश और ममता भी



1 नवंबर को कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन की महारैली 'दिल्ली चलो मार्च' में शामिल होंगे कई विपक्षी नेता अखिलेश और ममता बनर्जी के भी शामिल होने की संभावना विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन द्वारा 1 नवंबर को दिल्ली में महारैली निकाली जाएगी। जिस वजह से कई दुकानों को बंद रखने की घोषणा की गई है। जाहिर-सी बात है कि दिवाली जैसे पीक सीजन पर कमाई का एकमात्र जरिया बंद होने से व्यापारियों को खासा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसे लेकर CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने भी कहा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में हमारी 300 साल पुरानी मोहब्बत की दुकानें रैली के कारण बंद करवा रहे हैं, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। CTI चेयरमैन ने राहुल से की थी ये मांग CTI ने कहा था कि आप हमेशा बोलते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाता हूं, हमारी दुकानें भी ग्राहकों के साथ आपसी विश्वास, प्यार और मोहब्बत के आधार पर चलती है।

पंचकूला के स्कूल में खौफनाक घटना, KG की बच्ची को बेरहमी से पीटा; बेहोश होने पर भी नहीं रुका हमला

पंचकूला के एक स्कूल में KG की बच्ची पर तीसरी कक्षा के छात्र द्वारा हमले का वीडियो वायरल है। गंभीर रूप से घायल बच्ची PGI चंडीगढ़ में भर्ती है। पंचकूला के स्कूल में KG की बच्ची पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तीसरी कक्षा के छात्र पर पत्थर और गमले से हमला करने का आरोप। हरियाणा के पंचकूला के एक स्कूल से सामने आए वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला चर्चा में है। आरोप है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने KG की बच्ची को पत्थरों और गमले से बुरी तरह पीटा। बच्ची के बेहोश होने के बाद भी उस पर हमला किए जाने और उसे घसीटने का आरोप है। घटना में बच्ची गंभीर रूप से



घायल हो गई, जिसके बाद उसे PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो पंचकूला के एक स्कूल में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। मामले के सामने आने के बाद लोग स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीसरी कक्षा का छात्र KG में पढ़ने वाली बच्ची को स्कूल की पहली मंजिल पर ले गया था। आरोप है कि इसके बाद उसने पत्थरों से हमला किया और गमले से भी बच्ची को चोट पहुंचाई। बेहोश होने के बाद भी हमला करने का आरोप परिजनों के मुताबिक, बच्ची को काफी देर तक घसीटा गया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। इसके बाद उसे सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया। आरोपी छात्र ही परिजनों को बच्ची के पास लेकर पहुंचा बच्ची के चाचा फाजिल ने बताया कि परिवार के लोग जब बच्ची को तलाशते हुए स्कूल पहुंचे तो तीसरी कक्षा का वही छात्र उन्हें उसके पास लेकर गया, जिस पर हमले का आरोप है। परिजनों का दावा है कि छात्र बच्ची को उसके पिता के बुलाने का बहाना बनाकर पहली मंजिल पर ले गया था। स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल वहीं घटना के बाद बच्ची के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

दिल्ली में INDIA गठबंधन की रैली पर सस्पेंस, CTI ने अखिलेश ममता-उद्धव समेत नेताओं से की तारीख बदलने की मांग

CTI ने अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे समेत INDIA गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखा है। संगठन ने 1 नवंबर की रैली को 10-11 नवंबर के बाद आयोजित करने का आग्रह किया है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने INDIA गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखकर रैली स्थगित करने की मांग की है। इनमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे का नाम शामिल हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली रैली को 10-11 नवंबर के बाद के लिए टाल दिया जाए। CTI ने पार्किंग की कमी और ट्रैफिक में संभावित रुकावट का हवाला देते हुए कहा है कि दिवाली के दौरान इस रैली से 20 बाजारों में 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ सकता है। वहीं इससे पहले दूसरी ओर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे समेत अन्य नेता 1 नवंबर को रामलीला आने का ऐलान कर चुके है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या व्यापारियों की मांगें सुनी जाएगी या विपक्ष अपनी रैली की जिद पर अड़ा रहेगा। CTI ने नेताओं से क्या अपील की? CTI की ओर से दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों की ओर से इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखा। इसमें बताया कि इससे



पहले 3 पत्र CTI राहुल गांधी को भी लिखा गया लेकिन उन्होंने 1 नवंबर को ही रैली करने की जिद पकड़ रखी है। इसलिए उन्होंने नेताओं से अपील की है कि वे राहुल गांधी और कांग्रेस को समझाएं कि दिवाली के पीक सीजन में 10 लाख लोगों की महारैली करने से दिल्ली के व्यापारियों की दिवाली, काली हो सकती है, इसलिए रैली को दिवाली तक टालने का प्रस्ताव इंडिया गठबंधन की मीटिंग में लाया जाए। दिल्ली महारैली को लेकर दहशत का माहौल 1 नवंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की प्रस्तावित 10 लाख लोगों की महारैली को लेकर दिल्ली के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों की ओर से मांग है कि इस रैली को दिवाली बाद 10-11 नवंबर के बाद कर दिया जाए, 'हम रैली का विरोध नहीं कर रहे, हम दिवाली के पीक सीजन में अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। 6 नवंबर को धनतेरस है और 8 नवंबर को दिवाली है। 1 नवंबर उसकी तैयारी का सबसे पीक दिन है। अगर 1 नवंबर को 10 लाख लोग और 15-20 हजार वाहन मध्य दिल्ली में आए तो 20 ऐतिहासिक बाजारों में रोजाना होने वाला 10-12 हजार करोड़ का कारोबार ठप्प हो जाएगा। CTI की महारैली के 4 बड़े संकट कौन-से हैं? 1. रामलीला मैदान में पार्किंग का अभाव, हजारों वाहन कहां खड़े होंगे? रामलीला मैदान में 200 बड़ी बसों की भी पार्किंग नहीं है। 10 लाख लोगों को लाने के लिए 15,000 से 20,000 बसें, कारें, टेम्पो की जरूरत पड़ेगी, ये सभी वाहन JLN मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, अजमेरी गेट, चांदनी चौक रोड़ और इन सभी बड़े बड़े बाजारों के इर्द गिर्द खड़े होंगे तब भी जगह थोड़ी पड़ जाएगी, इससे सेंट्रल दिल्ली और पुरानी दिल्ली में चक्का जाम और लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं।

दिल्ली में 75 लाख लोगों की आजीविका दांव पर, CTI ने दिए कई विकल्प, पर नहीं सुन रहे राहुल गांधी

दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी की 1 नवंबर की रैली से व्यापारियों को कारोबार प्रभावित होने की चिंता है। CTI के मुताबिक, 12 हजार करोड़ रुपये तक का कारोबार खतरे में है। CTI रामलीला मैदान के आसपास के 20 बाजारों में पोस्टर अभियान शुरू करेगा। CTI चेयरमैन के मुताबिक, रैली से 20 लाख व्यापारियों पर असर पड़ सकता है। Ramlila Maidan Rally 1 November: चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस की रैली को लेकर कई बार राहुल गांधी को पत्र लिखे है, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। दिवाली जैसे बड़े त्योहार के बीच कांग्रेस की रामलीला मैदान की रैली व्यापारियों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। अब चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान के आसपास के 20 बाजारों में एक पोस्टर अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पोस्टर



अभियान के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अपील की जाएगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि 1 नवंबर को प्रस्तावित रैली से दिवाली के सीजन के कारोबार पर कोई असर न पड़े। 75 लाख लोगों की आजीविका प्रभावित CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि इस रैली से 20 लाख व्यापारियों पर असर पड़ सकता है, 10,000-12,000 करोड़ रुपये का कारोबार खतरे में पड़ सकता है और 75 लाख लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। 10,000-12,000 करोड़ रुपये का कारोबार और 75 लाख लोगों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। राहुल गांधी ने नहीं सुनी बात चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री अब तक राहुल गांधी को 3 पत्र लिख चुका है। इस पत्र में सीटीआई ने मांग की है कि कांग्रेस दिवाली के त्योहार के बाद यानी 10 नवंबर के बाद अपनी रैली आयोजित करें। हालांकि, राहुल गांधी ने रैली की तारीख को आगे बढ़ाने से मना कर दिया और कहा कि सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम रैली रोक देंगे। सोनिया गांधी के सामने की अपील जब राहुल गांधी के आगे बात नहीं बनीं तो व्यापारियों ने सोनिया गांधी के सामने अपील की। दिल्ली के चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की मेगा रैली को टालने का आग्रह किया है। रैली स्थल बदलने का दिया विकल्प चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कांग्रेस से मांग की कि वे कम-से-कम अपना प्रदर्शन स्थल बदल दें। उन्होंने विकल्प दिया कि रामलीला मैदान की जगह बुराड़ी ग्राउंड में रैली आयोजित की जाए। अपने पत्र में, CTI ने पार्किंग से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान में 200 बड़ी बसें खड़ी करने की भी जगह नहीं है, जबकि रैली के लिए अगर 10 लाख लोग आते है तो उनको लाने-ले जाने के लिए 15,000 से 20,000 बसों, कारों और टेम्पो की जरूरत होगी।

बंगाल की खाड़ी में बनेगा डिप्रेशन, अरुणाचल से आंध्र तक इन राज्यों में बारिश का अलर्ट



बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल सकता है। IMD ने अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और कई राज्यों में बारिश, आंधी-बिजली का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र 31 अक्टूबर को डिप्रेशन में बदल सकता है। दबाव क्षेत्र आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, अंडमान-निकोबार में व्यापक बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 31 अक्टूबर को, मौसम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र है, जो पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि 31 अक्टूबर के आसपास यह दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा उससे सटे अंडमान सागर के ऊपर और अधिक केंद्रित होकर एक 'डिप्रेशन' (गहरे कम दबाव के क्षेत्र) में बदल जाएगा। इसके बनने के बाद, अगले दो दिनों तक इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ते रहने की संभावना है।

ISRO का GSLV-F18 मिशन लॉन्च, NVS-03 सैटेलाइट से मजबूत होगी भारत की NavIC प्रणाली



श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F18 रॉकेट का प्रक्षेपण। NVS-03 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में स्थापित करने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको को दी बधाई। ISRO ने GSLV-F18 रॉकेट से NVS-03 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। इससे भारत की स्वदेशी NavIC प्रणाली मजबूत होगी और नेविगेशन सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी। ISRO ने GSLV-F18 यान, NVS-03 सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में स्थापित किया। NVS-03 अगली पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का तीसरा सैटेलाइट है, जिसे IRNSS श्रृंखला के लिए नेविगेशन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है।

प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर 10वीं की छात्रा पर मशीन से जानलेवा हमला; आरोपी गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश में प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज एक सिरफिरे ने स्कूल में घुसकर एक छात्रा पर मशीन से हमला कर दिया। छात्रा के साथ-साथ एक और छात्रा की हालत नाजुक बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश में प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर स्कूल में घुसकर छात्रा पर मशीन से हमला हमला करने वाला आरोपी बताया जा रहा पीड़िता का दूर का रिश्तेदार आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां रापथडू मंडल स्थित एक सरकारी स्कूल में घुसकर अज्ञात हमलावर ने दसवीं कक्षा की छात्रा पर लकड़ी काटने वाली इलेक्ट्रिक आरी (रंपा मशीन) से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, अपनी सहपाठी को बचाने पहुंची एक अन्य छात्रा भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई।



मिली जानकारी के मुताबिक, घटना शनिवार (31 अक्टूबर) की सुबह रापथडू स्थित जिला परिषद उच्च विद्यालय की है। स्कूल में सामान्य रूप से पढ़ाई चल रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात युवक परिसर में दाखिल हुआ और सीधे दसवीं कक्षा के कमरे में पहुंच गया। इससे पहले कि छात्र-छात्राएं कुछ समझ पाते, आरोपी ने वहां मौजूद छात्रा पर लकड़ी काटने वाली इलेक्ट्रिक आरी से हमला कर दिया। चेहरे, सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें हमले में छात्रा के चेहरे, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले में छात्रा का दाहिना हाथ भी कट गया। हमलावर ने उसके गले और कान के आसपास भी वार किए। इस दौरान दूसरी छात्रा ने अपनी सहपाठी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी घायल हो गई। अचानक हुई इस वारदात के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। छात्र और शिक्षक दहशत में आ गए। प्रेम प्रस्ताव ठुकराने के बाद किया जानलेवा हमला मिली जानकारी के अनुसार सिरफिरा युवक लड़की का दूर का रिश्तेदार लगता है। वो लड़की के एकतरफा प्रेम करने लगा। अपने प्रेम का इजहार जब उसने लड़की से किया तो लड़की ने उसका विरोध किया और वार्निंग भी दी। लड़का प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद से ही लड़की से बदला लेने की ठान लिया था। अस्पताल में चल रहा इलाज, घटना के बाद घायल छात्राओं को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल मुख्य पीड़िता को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अनंतपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

सम्पादकीय

अवसरों के विस्तार के बारह वर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के अनूठे दर्शन के अनुरूप, '2047 तक विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश के सभी समुदायों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों का मूल आधार है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखने, उच्च शिक्षा के द्वार खोलने और अनुसंधान एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिल सकती है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण सहायता, विदेश में अध्ययन के लिए प्रदान की गई सहायता और अनुसंधान फैलोशिप के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। विभाग का दृष्टिकोण वित्तीय बाधाओं को कम करने और शिक्षा की निरंतरता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। विभाग द्वारा उठाए गए कदम अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और बेरोजगार, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए अवसरों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वित्तीय सहायता के अलावा, छात्रवृत्ति प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से पारदर्शिता, लाभार्थियों के सत्यापन और सहायता के प्रत्यक्ष हस्तांतरण पर विशेष बल दिया गया है। स्कूली स्तर से ही शिक्षा के लिए सहायता अनुसूचित जाति और अन्य समुदायों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएससी) शैक्षणिक चक्र के प्रारंभिक चरणों में शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य साक्षरता को बढ़ावा देना, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और अनुसूचित जाति के बच्चों और उन बच्चों की स्कूली शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करना है जिनके माता-पिता या अभिभावक गंदे या खतरनाक व्यवसायों में लगे हुए हैं। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान 4,893 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता वितरित की गई है, और इस अवधि में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या लगभग तीन करोड़ है। केवल एक वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही 562 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे लगभग 27 लाख छात्रों को लाभ मिला है। इस योजना का उद्देश्य वंचित बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करके उनकी शिक्षा जारी रखने में सहायता करना है। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने की एक प्रमुख पहल है। इस प्रमुख पहल का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के बाद आगे की शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाना, छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करना और उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों की भागीदारी बढ़ाना है। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक 46,581 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है, जिससे लगभग 6.13 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, इस योजना के माध्यम से 47.53 लाख छात्रों को सहायता प्रदान की गई। डिजिटल सुधारों के माध्यम से पारदर्शिता को मजबूत करना वित्तीय वर्ष 2021-22 से छात्रवृत्ति नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली का समावेश है। इस प्रणाली के माध्यम से, छात्रवृत्ति राशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की जाती है। इस संशोधन का उद्देश्य जवाबदेही को मजबूत करना, सहायता प्राप्त करने में होने वाली देरी और धन की बर्बादी को कम करना और छात्रों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। डिजिटल सत्यापन इस ढांचे का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। नकली लाभार्थियों को सूची से हटाने की व्यवस्था नकली या डुप्लिकेट लाभार्थियों की पहचान करने में मदद कर रही है, जबकि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और इलेक्ट्रॉनिक 'अपने ग्राहक को जानें' सत्यापन पहचान सत्यापन में और सहायता प्रदान कर रहे हैं। DigiLocker और API Setu के साथ इसके एकीकरण से प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों के डिजिटल सत्यापन में सहायता मिल रही है। एक बार पंजीकरण से योजनाओं और शैक्षणिक वर्षों में लाभार्थियों की स्थिति का पता लगाना संभव हो गया है। शैक्षिक डेटाबेस से जुड़ाव से संस्थागत और छात्र अभिलेखों की वैधता की जांच में मदद मिलती है, वहीं यूआईडीएआई, एनपीसीआई और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जुड़ाव से बकाया भुगतान की प्रक्रिया में सहायता मिली है। इन सभी उपायों का संयुक्त प्रभाव प्रशासनिक प्रणालियों को मजबूत करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रवृत्ति सहायता योग्य छात्रों तक पहुंचे। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के द्वार खोलना प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा, 'स्कॉलरशिप फॉर यंग अचीवर्स स्कीम' (श्रेयस) इससे आगे बढ़कर कोचिंग, प्रतिष्ठित संस्थानों में विदेश में अध्ययन और अनुसंधान के अवसर प्रदान करती है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (एफटीएससी) के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण योजना, प्रतियोगी और व्यावसायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

संशोधन मांग रहा जनप्रतिनिधित्व कानून

डॉ. एके वर्मा। इस समय मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर का मुद्दा चर्चा में है। निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1950) की धारा 21 तथा निर्वाचक-पंजीकरण-नियम (1960) के नियम 25(1) के माध्यम से यह अधिकार प्राप्त है। आयोग तीन प्रकार से पुनरीक्षण कर सकता है। सामान्य पुनरीक्षण, विशेष पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण जिसमें मतदाता सूची से मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित आदि मतदाताओं के नाम हटाए और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। चूंकि विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची एकदम नए सिरे से बनाई जाती है, इसीलिए इसमें ज्यादा समस्याएं आती हैं। जमीनी स्तर पर बीएलओ आदि कर्मचारियों से त्रुटियां होती हैं, पर उसे वोट चोरी का नाम देना गलत है। मगर कुछ दलों ने राजनीतिक लाभ हेतु वोट चोरी का नैरेटिव चला रखा है। चुनाव आयोग वर्ष में चार बार-एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर-को 18 वर्षीय नागरिकों का मतदाता के रूप में पंजीकरण करता है। यहां तक कि यदि कोई नागरिक 17 वर्ष का है, तो भी वह अपना पंजीकरण करा सकता है, ताकि 18 वर्ष की आयु होने पर उसका नाम मतदाता सूची में स्वतः जुड़ जाए। अतः युवाओं को किसी गलतफहमी का



शिकार नहीं होना चाहिए। फिर भी, यदि किसी का नाम मतदाता सूची से कट गया है, तो वह फार्म-6 भर कर अपना नाम अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से जुड़वा सकता है। यदि चुनाव शुरू हो भी जाएं तब भी प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। जहां एक ओर चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अपडेट करने तथा महिलाओं, 85 वर्ष के मतदाताओं, दिव्यांगों और अन्य वैध-मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का अथक प्रयास करता है, वहीं कुछ लोग मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद इसलिए मतदान नहीं कर पाते, क्योंकि उनका नाम मतदाता-सूची से कट जाता है। कभी-कभी तो पूरा परिवार ही मतदाता सूची से गायब हो जाता है, जबकि उन सभी के पास मतदाता पहचान पत्र होता है। चुनाव आयोग 12 अन्य पहचान पत्रों को मान्यता देता है, जिससे मतदाता अपना नाम सूची में होने पर उन्हें दिखा कर मतदान कर सकता है। तब प्रश्न उठता है कि मतदाता पहचान पत्र का फिर क्या औचित्य? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) को 1958 में संशोधित कर मतदाता पहचान पत्र को कानूनी-वैधता प्रदान की गई। चुनाव आयोग का मतदाता पहचान पत्र विशेष होता है, उस पर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो मतदाता सूची में मतदाता के नाम पर भी अंकित होता है। अन्य किसी पहचान पत्र में वह नंबर नहीं होता। अतः आयोग के अधिकारी 'चेक' कर सकते हैं कि किसी मतदाता पहचान पत्र के अल्फा न्यूमेरिक नंबर का क्या हुआ? क्यों वह हटाया गया? क्या वह कहीं और चला गया या किसी दूसरी जगह उसका मतदाता पहचान पत्र बना है? जिन मतदाताओं के नाम गलती से सूची से कट गए, वे अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करें? क्या उनका तत्काल पंजीकरण कर मतदान सुनिश्चित नहीं किया जा सकता? इसमें जनप्रतिनिधित्व कानून (1951) की धारा 62(1) एक अवरोध है, जो नागरिकों का मतदान अधिकार परिभाषित करता है। इसके अनुसार 'केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकता, जिसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता-सूची में है'। यह कानून 75 वर्ष पुराना है जब मतदाता-सूची के अतिरिक्त मतदाता रिकार्ड का कोई और विकल्प न था। जबकि 1993 से मतदाता पहचान पत्र मतदाता होने का ठोस प्रमाण है। जब मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र दोनों ही चुनाव आयोग जारी करता है, तो फिर उनका स्तर और मान्यता एकसमान क्यों नहीं? अब आयोग को तय करना है कि मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद मतदाता सूची में नाम न होने पर वोट न दे पाने की समस्या का हल कैसे निकाला जाए। जिस तत्परता से आयोग अधिक से अधिक मतदान की कोशिश करता है, लेकिन उसे इसके लिए अपनी कोशिशों का दायरा बढ़ाना ही होगा।

चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं का अनवरत पंजीकरण (फार्म-6), पंजीकरण स्थानांतरण (फार्म-8) और 17 वर्ष की अवस्था की स्थिति में पूर्व-पंजीकरण भारत में मतदाता पंजीकरण को सरल बनाती है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। देश-विरोधी तत्वों और भ्रष्ट प्रशासनिक कर्मचारियों की मिलीभगत से अपात्र लोग भी मतदाता पहचान पत्र बनवा लेते हैं।

जोखिम बढ़ाता बढ़ता व्यापार घाटा

डॉ. जयंतीलाल भंडारी। हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे की चुनौती का सामना कर रहा है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2015-16 के 52.5 अरब डालर से दोगुने से अधिक होकर 2025-26 में 112 अरब डालर हो गया। हालांकि चीन को भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है, लेकिन वहां से आयात की बड़ी मात्रा व्यापार घाटे को और बढ़ा रही है। चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक असंतुलन के पीछे कई संरचनात्मक और नीतिगत कारक जिम्मेदार हैं। इसका प्रमुख कारण चीन की गैर-शुल्क बाधाएं हैं। वित्त मंत्री के अनुसार, चीनी प्रशासन के जटिल तकनीकी, स्वास्थ्य और गुणवत्ता मानक भारतीय वस्तुओं के चीनी बाजार में प्रवेश को बाधित करते हैं। भारत एक दशक से अधिक समय से अपनी जेनेरिक दवाओं, प्रसंस्कृत मांस और कृषि उत्पादों के लिए चीनी बाजार में उचित पहुंच की मांग करता रहा है। जबकि चीन घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए जटिल नियम लागू करता है। इसके चलते भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धी कीमतों और गुणवत्ता के बावजूद चीनी बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाते। इसके अलावा चीनी युआन की विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ता है। चीन के साथ व्यापारिक असंतुलन का एक अन्य पहलू 'मेक इन इंडिया' अभियान के बावजूद



चीनी कच्चे माल और घटकों पर भारत की निर्भरता है। हालांकि भारत का घरेलू विनिर्माण क्षेत्र हाल के वर्षों में बढ़ा है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन अब भी चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है। भारत का इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, डिस्प्ले पैनल, सोलर पीवी सेल, औषधीय कच्चा माल यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रीडिएंट्स (एपीआइ) और भारी औद्योगिक मशीनरी के लिए चीन से आयात पर निर्भरता बनी हुई है। इस निर्भरता के कारण भारत में औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण बढ़ने के साथ चीनी कलपुर्जों का आयात भी बढ़ता है। साथ ही चीन ने दुर्लभ मृदा तत्वों, लीथियम और आधुनिक उर्वरकों के उत्पादन एवं निर्यात पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। ये संसाधन भारत के इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं। इनकी सीमित आपूर्ति और ऊंची कीमतों के कारण भारत को हर साल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए केवल जवाबी सीमा शुल्क लगाना दीर्घकालिक समाधान नहीं है। इसके बजाय भारत को व्यापक रणनीति अपनानी होगी। इसकी पहली प्राथमिकता इलेक्ट्रानिक्स और सेमीकंडक्टर का घरेलू इकोसिस्टम विकसित करना होना चाहिए। भारत को अंतिम उत्पादों की असेंबलिंग के बजाय घटक स्तर पर निर्माण बढ़ाना होगा। जब तक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एडवांस्ड सेंसर, डिस्प्ले पैनल और सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन देश में शुरू नहीं होता, तब तक चीन पर निर्भरता समाप्त नहीं होगी। दूसरा कदम फार्मास्यूटिकल्स और बल्क ड्रग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन उसका दवा उद्योग एपीआइ के लिए 70 प्रतिशत तक चीन पर निर्भर है। यह निर्भरता रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा करती है। इस निर्भरता को कम करने के लिए देश में घोषित बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना तेज करनी होगी और 41 महत्वपूर्ण एपीआइ के घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू करनी होंगी। साथ ही चीन की गैर-शुल्क बाधाओं का मुकाबला करने के लिए भारत को कूटनीतिक प्रयासों के साथ देश में क्वालिटी कंट्रोल आर्डर लागू करने होंगे। अमानक चीनी सामान की डंपिंग रोकने के लिए गुणवत्ता मानक तय करना जरूरी है, ताकि घरेलू विनिर्माताओं को प्रतिस्पर्धा का उचित माहौल मिल सके। भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और 'फ्रेंड-शोरिंग' की नीति अपनानी होगी। क्रिटिकल मिनरल्स, दुर्लभ धातुओं और उच्च तकनीकी उत्पादों के लिए चीन पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से समान विचारधारा वाले देशों के साथ वैकल्पिक आपूर्ति नेटवर्क तैयार करना होगा। ग्रीन टेक्नोलाजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार के दौर में यदि भारत ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा नहीं दिया तो जीवाश्म ईंधन के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम होने के बाद चीन से हरित प्रौद्योगिकी के आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। चीन से बढ़ता व्यापार घाटा केवल आयात-निर्यात का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्थिरता, औद्योगिक क्षमता और रणनीतिक संप्रभुता से जुड़ा विषय है। इसीलिए हमें घरेलू वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता बनाना होगा। हमें चीन को आर्थिक प्रतिस्पर्धी मानते हुए उससे मुकाबले के प्रयास करने होंगे।

उद्योग और कारोबार में शोध एवं नवाचार के लिए संसाधन बढ़ाने होंगे।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन, गुणवत्ता मानकों के पालन तथा व्यापारिक साझेदारों के विविधीकरण के प्रयासों को गति देनी होगी।

रश्मिका मंदाना की फिल्म मैसा का नया धमाका, इस दिन रिलीज होगा फर्स्ट सॉन्ग ओ मैसा रे

रश्मिका मंदाना की फिल्म 'मैसा' का पहला गाना 2 नवंबर को रिलीज होगा। रश्मिका मंदाना की फिल्म 'मैसा' गाने का नाम 'ओ मैसा रे' रखा गया है। फिल्म की कहानी आदिवासी कहानी और पिता-बेटी के रिश्ते पर आधारित है। साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म को लेकर खासी सुर्खियों में बनी हुई हैं। भारत की पहली फीमेल-लेड पैन-इंडिया फिल्मों में शुमार इस प्रोजेक्ट का नाम 'मैसा' है, जो सिनेमाघरों में 27 नवंबर 2026 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म के टीजर को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद अब मेकर्स ने इसके फर्स्ट सॉन्ग की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान ने दर्शकों की उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट पारंपरिक एक्शन फिल्मों से काफी अलग होने वाला है। बाप और बेटी के अनोखे रिलेशन की कहानीअब



तक भारतीय सिनेमा में बाहुबली या केजीएफ जैसी कई बड़ी एक्शन फिल्में आई हैं, जिनमें अहम रूप से मां और बेटे के रिश्ते की भावनात्मक गहराई को पर्दे पर दिखाया गया है। हालांकि 'मैसा' इन सभी से बिल्कुल अलग एक नए ट्रैक पर चलने वाली है। इस फिल्म की कहानी आदिवासी कहानी पर बुनी गई है, जिसमें एक पिता और बेटी के बीच के अटूट और मजबूत रिश्ते को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पिरोया गया है। डायरेक्टर रवींद्र पुल्ले इस अनोखी कहानी के जरिए दर्शकों को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देने जा रहे हैं जो हिंदी और साउथ सिनेमा में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है। टीजर की रॉ एनर्जी और जबरदस्त सक्सेस फिल्म मैसा के मेकर्स ने जब इसका टीजर दुनिया के सामने पेश किया था, तब से ही इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। क्रिटिक्स और आम दर्शकों दोनों ने ही इसकी रॉ एनर्जी, ग्रैंड स्केल और इंटेंस एटमॉस्फियर की खुलकर सराहना की है।टीजर में रश्मिका मंदाना का एक ऐसा रूप देखने को मिला है, जिसे उन्होंने अपने अब तक के करियर में कभी नहीं अपनाया था। उनकी इस खौफनाक और दमदार परफॉर्मेंस ने फिल्म के प्रति उम्मीदों को कई गुना बढ़ा दिया है। बड़े पर्दे पर इस तरह के विजुअल्स देखना वाकई सिने प्रेमियों के लिए एक अलग अनुभव होने वाला है। रश्मिका मंदाना की फिल्म 'मैसा' 27 नवंबर 2026 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। ओ मैसा रे सॉन्ग से बढ़ेगी हलचल रश्मिका मंदाना की फिल्म मैसा के टीजर की सक्सेस के बाद अब दर्शकों का इंतजार पहले सॉन्ग को लेकर खत्म होने जा रहा है। मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा कर दी है कि फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग 'ओ मैसा रे' 2 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। इस गाने के सामने आए पोस्टर में आग के बीच एक दिलचस्प सिल्हूट नजर आ रहा है, जो इसकी तेज एनर्जी की एक बेहतरीन झलक पेश करता है। फेमस संगीतकार जैक्स बिजॉय ने इस गाने को अपनी धुनों से सजाया है, जो फिल्म के देसी और रॉ माहौल को और ज्यादा प्रभावी बनाने का काम करेगा।

भंसाली ने सलमान खान-ऐश्वर्या राय की पुरानी मोहब्बत को करवा चौथ पर किया याद, पोस्ट पर यूजर्स ने उठाए सवाल



भंसाली प्रोडक्शंस ने करवा चौथ पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की पुरानी तस्वीरें शेयर कीं। ये तस्वीरें फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के गाने 'चांद छुपा बादल में' की हैं। पोस्ट के कैप्शन में प्रोडक्शन हाउस ने लिखा, 'कुछ तस्वीरें, कुछ यादें और मोहब्बत का एक खूबसूरत अफसाना।' करवा चौथ के मौके पर बॉलीवुड की एक पुरानी जोड़ी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। दरअसल, संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस भंसाली प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सुपरहिट गाने 'चांद छुपा बादल में' की हैं। तस्वीरों में सलमान और ऐश्वर्या की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। हालांकि, इन तस्वीरों को शेयर करना प्रोडक्शन हाउस को भारी पड़ गया और सोशल मीडिया यूजर्स ने उसे जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

'तुम्हारी याद में कांटे 2 बनाऊंगा', दोस्त संजय गुप्ता के जाने से टूटे संजय दत्त, शेयर किया भावुक पोस्ट

संजय गुप्ता के निधन से भावुक संजय दत्त ने 'कांटे 2' बनाने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि यह फिल्म उनके दोस्त का सपना थी और वह इसे पूरा करने के लिए हर कोशिश करेंगे। फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन से अभिनेता संजय दत्त भावुक हो गए। संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर की। बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके अचानक चले जाने से परिवार, दोस्तों और फिल्मी सितारों को गहरा सदमा पहुंचा है। इस बीच अभिनेता संजय दत्त ने अपने करीबी दोस्त को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने न सिर्फ संजय गुप्ता के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया, बल्कि उनसे जुड़ा एक खास वादा भी किया है। संजय दत्त ने कहा है कि वह अपने दोस्त के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए 'कांटे 2' बनाएंगे। संजय दत्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संजय गुप्ता के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके भाई जैसे दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों ने साथ में कई साल बिताए, ढेर सारी यादें बनाई और जिंदगी के कई उतार-चढ़ाव एक साथ



देखे।

संजय दत्त का पोस्ट संजय दत्त ने अपने पोस्ट में लिखा, 'गुप्ट्स, मेरे भाई. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम चले गए हो. हमने साथ में बहुत कुछ शेयर किया है, इतनी सारी यादें और दोस्ती के इतने सारे साल. तुम हमेशा मेरे लिए परिवार की तरह रहे हो।' उन्होंने आगे कहा कि वह अपने दोस्त को, उनके साथ हुई बातचीत और साथ बिताए पलों को हमेशा याद करेंगे। अभिनेता ने बताया कि दोनों कुछ समय पहले 'कांटे 2' को लेकर बातचीत कर रहे थे। संजय गुप्ता का सपना था कांटे 2 संजय दत्त ने अपनी पोस्ट में एक खास खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले ही दोनों के बीच फिल्म 'कांटे 2' को लेकर बातचीत हुई थी। यह फिल्म संजय गुप्ता का सपना थी और वह इसका दूसरा पार्ट बनाना चाहते थे। अब उनके निधन के बाद संजय दत्त ने इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। दोस्त की याद में संजय दत्त ने किया बड़ा वादा संजय दत्त ने भावुक होते हुए लिखा कि वह संजय गुप्ता की याद में 'कांटे 2' को उनका सपना बनाएंगे और इसे सच करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि दोस्त के जाने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी और वह उन्हें हमेशा प्यार करते रहेंगे। बता दें कि संजय गुप्ता और संजय दत्त ने 'कांटे' समेत कई फिल्मों में साथ काम किया था। दोनों की दोस्ती भी काफी पुरानी थी। ऐसे में संजय दत्त का यह वादा उनके दोस्त के प्रति प्यार और सम्मान को बयां करता है।

विनेश फोगाट की याचिका पर दिल्ली होई कोर्ट का WFI को नोटिस, दो सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया



दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को पहलवान विनेश फोगाट को 9 मई और 17 जून को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने WFI को जारी किया नोटिस विनेश फोगाट की याचिका पर नोटिस जारी किया गया कारण बताओं नोटिस पर दो हफ्ते में फैसला लेने को कहा दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ को पहलवान विनेश फोगाट को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

भारतीय टीम की हार के बीच अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास, तोड़ डाला जोश लिटिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

अर्शदीप सिंह 2026 में सबसे ज्यादा 40 विकेट लेने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 87 रनों से हरा दिया ऑकलैंड में शुक्रवार को खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 87 रनों से हरा दिया है. इस मैच में कीवियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों का पहाड़ खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट खोकर 172 रन ही बना सकी।

इस हार के साथ टीम इंडिया को टी20 इंटरनेशनल में अपनी दूसरी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ भारत को 125 रनों की सबसे बड़ी हार मिली थी। हालांकि, इस करारी हार के बीच भी भारतीय



तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एक ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसने दुनिया भर के दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड दरअसल, इस मुकाबले में जहां अन्य गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही थी, वहीं अर्शदीप सिंह ने बेहद किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 38 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इस एक विकेट के साथ ही अर्शदीप अब एक कैलेंडर वर्ष 2026 में सबसे ज्यादा 40 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने आयरलैंड के जोश लिटिल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने साल 2022 में 39 विकेट चटकाए थे। इस सूची में श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा 38 विकेट साल 2024 के साथ तीसरे और भारत के भुवनेश्वर कुमार 37 विकेट साल 2022 के साथ चौथे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्शदीप सिंह के टी20 इंटरनेशनल करियर का 150वां विकेट था T20I में पूरे किए 150 विकेट आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मिला यह विकेट अर्शदीप सिंह के टी20 इंटरनेशनल करियर का 150वां विकेट था। वह इस आंकड़े को छूने वाले भारत के पहले और दुनिया के नौवें गेंदबाज बन गए हैं। इतना ही नहीं, अर्शदीप डेब्यू के बाद सबसे कम दिनों में 150 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं।

यूएस-ईरान के बीच डील के लिए ड्राफ्ट तैयार! परमाणु को लेकर अमेरिका ने रखा बड़ी शर्त

अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत के लिए मसौदा तैयार किया गया परमाणु को लेकर डील में बड़ी शर्त होने का दावा अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए एक प्रारंभिक मसौदा तैयार किया गया है जिसमें ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को किसी सहमत तीसरे देश को हस्तांतरित करने या उसके संवर्धन स्तर को कम करने का प्रस्ताव है, साथ ही प्रारंभिक सहमति के सात दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए फिर से खोलने का भी प्रस्ताव है। अल अरबिया इंग्लिश की रिपोर्ट के अनुसार, चीन किसी भी समझौते के कार्यान्वयन और स्थिरता के लिए गारंटर के रूप में कार्य कर सकता है। इस मसौदे में इस्तांबुल के बजाय दोहा में अमेरिका-ईरान की सीधी वार्ता आयोजित करने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा पर उठाए गए कदमों के जवाब में अमेरिका प्रतिबंधों, नाकाबंदी और आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने के लिए कदम उठाएगा। प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंच गया एक स्वतंत्र सत्यापन तंत्र, कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण से पहले अनुपालन का आकलन करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पक्ष संबंधित, स्वतंत्र रूप से सत्यापित प्रतिबद्धताओं के बिना महत्वपूर्ण रियायतें न दे। रिपोर्ट के अनुसार, मसौदे में विलंब या उल्लंघन को दूर करने और नए सिरे से सैन्य तनाव को रोकने के लिए मध्यस्थों और गारंटर पक्षों को शामिल करते हुए एक विवाद-समाधान तंत्र का भी प्रस्ताव है। आईआरएनए के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम बहाल करने के प्रयास में कतर का एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंच गया है। कतर के



प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के एक वरिष्ठ सलाहकार के नेतृत्व में और वाशिंगटन के समन्वय से काम कर रहे इस प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार सुबह परामर्श के लिए तेहरान में कदम रखा। ट्रंप ने युद्ध को लेकर दिया बयान इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा ईरानी सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेजाई को कतरी दूतों द्वारा दिया गया पत्र तेहरान में स्वागत के योग्य बताया गया है, जिसमें आगे अमेरिकी सैन्य हमलों को रोकने के लिए एक नए राजनयिक मार्ग का प्रस्ताव है। यह मसौदा ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वाशिंगटन ईरान के साथ अपने युद्ध को समाप्त करने में कोई जल्दी नहीं कर रहा है, और चल रही शत्रुता को "एक सामान्य युद्ध नहीं" बताते हुए कहा है कि महीनों की लड़ाई और बार-बार किए गए राजनयिक प्रयासों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है, फिर भी समय अमेरिकी पक्ष के पक्ष में है। होर्मुज खोलने को लेकर भी प्रस्ताव शामिल ट्रंप का दावा वे बात करना चाहते हैं ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि तेहरान अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक है, लेकिन उसे घरेलू स्तर पर गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से सैन्य कर्मियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को वेतन देने में असमर्थता का जिक्र करते हुए। ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा, "बातचीत चल रही है। वे बात करना चाहते हैं। वे बात करते रहते हैं।" "लेकिन देखिए, वे अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे रहे हैं, वे अपनी पुलिस को वेतन नहीं दे रहे हैं। वे बहुत मुश्किल में हैं। और सच कहें तो हमारे पास समय है। यह एक युद्ध है, लेकिन यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है; हम वहां सात महीने से हैं।

पुतिन से डीजल डील होते ही बदले अमेरिका के सुर, पेंटागन ने यूरोपीय देशों को चेताया



पेंटागन ने यूरोपीय नेताओं को रूस के खिलाफ बयानबाजी में संयम की सलाह दी एल्ब्रिज कोल्बी ने बाल्टिक देशों के अधिकारियों तक यह संदेश पहुंचाया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक महीने पहले रूस को दुनिया से अलग-थलग करने के लिए रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की योजना बना रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने खुद रूस से एक बड़ी तेल डील कर ली। इसके बाद से ही रूस को लेकर ट्रंप प्रशासन के सुर पूरी तरह बदल गए हैं। इसी बीच खबर आई है कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों को रूस के खिलाफ बयानबाजी से बचने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के अधिकारियों ने यूरोपीय नेताओं को रूस के खिलाफ उकसावे वाली बयानबाजी करने से बचने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यूरोपीय नेताओं के कुछ बयान महाद्वीप की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं हैं। यूरोपीय सरकारों को सख्त चेतावनी जानकारी के मुताबिक, पेंटागन ने लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया समेत कई यूरोपीय देशों के नेताओं को रूस के खिलाफ कोई भी बयान देते समय संयम बरतने को कहा है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि पेंटागन की ओर से यह हिदायत बाल्टिक देशों के अलावा और किन यूरोपीय सरकारों को दी गई है। पेंटागन के नीति प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बी भी यह संदेश देने वाले अमेरिकी अधिकारियों में शामिल थे। कोल्बी यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की समीक्षा से जुड़े अहम अधिकारी हैं। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए रूस से बातचीत की कोशिश कर रहा है एल्ब्रिज कोल्बी ने यूरोपीय देशों से क्या कहा? जानकारी के मुताबिक, एल्ब्रिज कोल्बी ने बाल्टिक देशों के एक अधिकारी से रूस के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने की सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, कोल्बी ने इस दौरान अधिकारी को उन बयानों का उदाहरण दिया, जिनमें कहा गया था कि यूक्रेन युद्ध में रूस बुरी तरह फंस चुका है और हताश होकर कदम उठा रहा है।

अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बैठक का दौर, होर्मुज खुला रखने पर चर्चा; G20 और क्वाड का एजेंडा समझे

अमेरिका के अटलांटा में विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक जी20 के नेताओं के साथ विदेश मंत्री ने बैठक की विदेश मंत्री एस जयशंकर जी20 सम्मेलन के लिए अटलांटा पहुंचे हैं। वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा आयोजित दो दिवसीय विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए शुक्रवार को पहुंचे। रिपोर्ट के अनुसार, बैठक का एजेंडा ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री मार्गों को खुला रखने पर केंद्रित है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका भारत के तेल, एलएनजी और उर्वरक आयात पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जयशंकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लेंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सूत्रों के अनुसार, उनकी सूची में यूरोप, मैक्सिको, पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका शामिल हैं, जो दर्शाता है कि भारत एक अस्थिर विश्व में अपने विकल्पों को व्यापक बनाने का प्रयास कर रहा है। अहम मुद्दों पर बातचीत संभव सूत्रों के अनुसार फिलहाल अमेरिका के साथ



कोई औपचारिक द्विपक्षीय बैठक नहीं है, क्योंकि रूबियो ने हाल ही में भारत का दौरा किया है। दोनों देशों के बीच आमने-सामने की बैठक होने की प्रबल संभावना है। क्वाड बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आ रहे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व अटलांटा में रूबियो, जापान के तोशिमित्सु मोटेगी और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक में समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। हॉर्मुज को लेकर बैठक में चर्चा हुई जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात सूत्रों के अनुसार, दो दिनों के दौरान जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल से भी मुलाकात करेंगे। बर्लिन यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग और कुशल प्रवासन जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों पक्षों द्वारा भारत-यूरोपीय संघ के घनिष्ठ आर्थिक संबंधों का अधिकतम लाभ उठाने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी।

इजरायल में मुसलमान कहां से आए? ये तो यहूदियों का देश



इजरायल की कुल आबादी में करीब 20 प्रतिशत अरब मूल के लोग हैं, जिनमें 80 प्रतिशत मुस्लिम हैं। 1948 में इजरायल बनने के बाद यहां रह गए अरब परिवारों को नागरिकता मिली और वे इजरायली अरब कहलाए। जमीन, गरीबी और कथित भेदभाव के बावजूद अरब पार्टियां इजरायल की राजनीति में अहम भूमिका निभा रही हैं। इजरायल के हालिया आम चुनाव में अरब नेतृत्व वाली पार्टियां किंगमेकर बनकर उभरी हैं। 120 सीटों वाली इजरायली संसद में अरब पार्टियों ने कुल 19 सीटें जीती हैं। ऐसे में सरकार गठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद को यहूदियों का देश बताने वाले इजरायल में करीब 20 प्रतिशत आबादी अरब मूल के लोगों की है और इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं? आखिर इजरायल में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी कैसे पहुंची और वहां रहने वाले अरब नागरिकों की स्थिति कैसी है? दरअसल, इसकी कहानी 1948 में इजरायल के गठन से जुड़ी है।

इस्तांबुल में फोटोशूट के दौरान गुब्बारों के साथ उड़ने लगी दुल्हन; फोटोग्राफर ने तेज हवा में लगाई दौड़

तेज हवा के कारण गुब्बारे संग उड़ी दुल्हन सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल वेडिंग फोटोशूट के दौरान तेज हवा ने ऐसा खेल दिखाया कि फोटोशूट के दौरान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले तो सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। क्रीम कलर के गाउन में महिला क्रीम कलर के ढेर सारे गुब्बारे हाथों में लेकर फोटोशूट कराने के लिए पोजेज दे रही है। इतने में अचानक हवा की रफ्तार तेज हो जाती है। फिर क्या था, पूरे भीड़ को मानों चीरते हुए महिला आगे की ओर बढ़ी जा रही है। मानों अगर कोई न रोके तो वो भी गुब्बारे के साथ उड़ती चली जाती। ये 30 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। लोग उस फोटोग्राफर की तारीफ कर रहे



हैं जिसने कैमरा छोड़कर महिला को बचाया। फोटोग्राफर ने दुल्हन को ऐसे बचाया भारत देश में ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई हैरान हो रहा है कि जो फोटोग्राफर बेचारा पीछे छूट गया था उसने इतने कम टाइम में कैमरे को छोड़कर कैसे महिला को बचा लिया। खास बात जो वीडियो में दिखाई दे रही है कि महिला के आगे कई लोग खड़े थे। चाहते तो आगे खड़े लोग भी महिला की मदद कर सकते थे। लेकिन महिला गुब्बारे संग भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। ऐसे में वो एक शख्स जिसने मदद की वो था फोटोग्राफर। सोशल मीडिया पर हर कोई इस फोटोग्राफर की तारीफ कर रहा है। उड़ती गई महिला और भीड़ ने बनाया वीडियो इस वेडिंग फोटोशूट वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा है कि जहां एक ओर बेचारी महिला गुब्बारे संग उड़ती जा रही है, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि अब खुद को कैसे बचाया जाए।

देखा जाए तो अगर फोटोग्राफर उसे बचाने नहीं आता तो शायद आज कोई बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि आसपास खड़ी भीड़ वीडियो बनाने में व्यस्त हो गई थी।

ऐसे में हमें इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई परेशानी में है तो पहले उसकी मदद करें, उसकी जान बचाएं और फिर वीडियो बनाए। ध्यान रखें, वीडियो बनाने से ज्यादा जरूरी किसी की जिंदगी को बचाना है।

Gold-Silver की कीमतों में भारी गिरावट, सोने-चांदी के सस्ता होने की क्या है वजह? आगे गिरेगा भाव या आएगी तेजी!

धनतेरस-दिवाली से पहले कीमती धातुओं के दाम में आई इस गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों का ध्यान खींचा है। खास बात यह है कि चांदी की कीमतों में सोने के मुकाबले ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। त्योहारों के सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट चांदी की कीमतों में सोने के मुकाबले ज्यादा गिरावट पीएम मोदी की अपील के बाद सोने-चांदी की खरीद में आई कमी का दावा भारत देश में लोगों को आभूषण पहनने का शौक है। शादी, ब्याह, किसी शुभ कार्य या फिर त्योहारों के मौके पर लोग सोने और चांदी के गहने खरीदते है। सोने-चांदी के



कीमतों में बढ़ोत्तरी जब होती तो आमजनता इसके खरीद से परहेज करती है और सोने-चांदी के भाव कम होने का इंतजार करती है। बीते कुछ महीनों की बात करें तो सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे थे। वैश्विक उथल-पुथल के समय देश की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भावुक अपील करते हुए कहा था कि देश की जनता अगर सालभर सोने और चांदी को खरीदने से बचेगी तो वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति बहुत मजबूत होगी। जनता ने भी वैश्विक अघोषित आपात में देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए सोने और चांदी की खरीद में कमी की। इसका परिणाम भी देखने को मिला। मौजूदा समय में त्योहारों के सीजन में जहां हर बार सोने और चांदी के दाम आसमान छूते है तो वहीं इस बार बीते कुछ दिनों से दाम कम हो रहे है। त्योहारी सीजन और धनतेरस-दिवाली से पहले कीमती धातुओं के दाम में आई इस गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों का ध्यान खींचा है। खास बात यह है कि चांदी की कीमतों में सोने के मुकाबले ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है।

छत्रपति संभाजीनगर की 32 कंपनियों का बाजार मूल्य 10.79 लाख करोड़ के पार, शेयरों में 15 गुना तक उछाल

संभाजीनगर से जुड़ी 32 सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य 10.79 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। क्षेत्र में 86 हजार से अधिक MSME भी सक्रिय हैं। जिले में 86,429 MSME से करीब 4,04,838 लोगों को रोजगार मिला है। ल्यूमैक्स ऑटो के शेयर में पांच वर्षों में लगभग 1471% की वृद्धि दर्ज की गई है। गरवारे हाईटेक फिल्म्स के शेयर में 710% से अधिक की तेजी आई। ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन के लिए पहचाने जाने वाले छत्रपति संभाजीनगर की पहचान अब देश के



औद्योगिक और आर्थिक मानचित्र पर भी तेजी से मजबूत हो रही है। शहर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित कंपनियों ने उत्पादन के साथ-साथ पूंजी बाजार में भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। ऑटोमोबाइल, वाहन कलपुर्जे, औषधि निर्माण, अभियांत्रिकी, इस्पात और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों की 32 सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य 10.79 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है। इनमें कई कंपनियों के शेयरों ने पिछले पांच वर्षों में दो से लेकर 15 गुना तक की वृद्धि दर्ज की है। यह आंकड़े क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता और आर्थिक महत्व को नई पहचान दे रहे हैं। 32 कंपनियां, 10.79 लाख करोड़ का बाजार मूल्य उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, छत्रपति संभाजीनगर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी 32 कंपनियां राष्ट्रीय शेयर बाजार और मुंबई शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। इनमें बजाज ऑटो, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क फार्मा, वॉकहार्ट, अजंता फार्मा, आईपीसीए लैबोरेटरीज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, वेरॉक इंजीनियरिंग, ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, गरवारे हाईटेक फिल्म्स और एथर एनर्जी जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य लगभग 10 लाख 79 हजार 368 करोड़ रुपये आंका गया है। हालांकि, इन कंपनियों के उत्पादन केंद्र देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भी हैं। इसलिए उनके पूरे बाजार मूल्य का श्रेय केवल छत्रपति संभाजीनगर को नहीं दिया जा सकता।

म्हाडा के ठेकेदारों को मिलेगी

कर अधिकतम पांच दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। इस प्रक्रिया में फाइल को अनावश्यक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित लेखाधिकारी को ही भुगतान से जुड़ा निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इस तरह बिल जमा होने से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया अधिकतम 20 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई म्हाडा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी ठोस कारण के बिलों का भुगतान लंबित रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जिन अधिकारियों के पास बिल मंजूर करने का अधिकार नहीं है, उनके पास फाइल भेजकर प्रक्रिया में देरी करने को भी गंभीरता से लिया जाएगा। निर्माण कार्यों को मिलेगी गति मुंबई शहर म्हाडा के इस फैसले से ठेकेदारों को समय पर भुगतान मिलने की उम्मीद है। भुगतान में देरी के कारण निर्माण कार्यों की गति प्रभावित होती है। नई व्यवस्था से ठेकेदारों को आर्थिक राहत मिलने के साथ आवासीय और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने में मदद मिल सकती है।

शिंदे के साथ खिलवाड़ शुरू

शिक्षक और स्नातक चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। महायुति में बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में बढ़ते तनाव के बीच विधानसभा में कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने नमक रगड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से शिंदे को सताना शुरू किया है। उनका दावा है कि असल में बीजेपी अब शिंदे से पीछा छुड़ाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर ली है और सहयोगी दल के कई नेता उनके संपर्क में हैं। विधान परिषद की पुणे पदवीधर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की हार के बाद सहयोगी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। चुनाव में उप मुख्यमंत्री शिंदे की शिवसेना की भूमिका से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नाराज बताए जा रहे हैं। इसका परिणाम गुरुवार को तब देखने मिला जब सीएम देवेंद्र दादर में आयोजित एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ मंच साझा करते नजर आए। कार्यक्रम से पहले सीएम देवेंद्र ने ठाकरे बंधुओं के साथ बंद कमरे में लगभग आधे घंटे तक गुप्त रूप से चर्चा भी की। इसके उपरांत कार्यक्रम में भी चुटकी लेने के बावजूद ठाकरे बंधुओं के साथ फडणवीस आत्मीयता से मिलते नजर आए, जिसकी वजह से अटकलों का बाजार गरम है। सतर्क हुए शिंदे गठबंधन में बढ़ते विवाद और राज उद्धव ठाकरे के साथ हुई सीएम देवेंद्र की आत्मीय मुलाकात की पृष्ठभूमि में अब शिवसेना नेतृत्व सतर्क हो गया है। डीसीएम शिंदे ने अपनी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को सहयोगी दलों पर बयानबाजी से बचने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोस्ती में कुश्ती नहीं होनी चाहिए और विवाद को खत्म करने के लिए वरिष्ठ स्तर पर बातचीत की जाएगी। शिवसेना प्रवक्ता आनंद परांजपे ने बीजेपी नेताओं से संयम बरतने को कहा है। कलह के नाम पर हो रहा बड़ा खेला पुणे स्नातक सीट पर एनसीपी (शरद पवार) की हर्षदा देशमुख ने बीजेपी की स्मिता जाधव को 9,928 वोटों से हराया था। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना के नेताओं में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। महायुति की अंदरूनी कलह पर तंज कसते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि बीजेपी नीत सरकार में जानबूझकर शिंदे की शिवसेना के मंत्रियों, विधायकों के साथ चुनाव बाद राजनीति खेली जा रही है। दोनों दलों के बीच संवाद खत्म हो चुका है। वडेट्टीवार ने महायुति की तुलना झगड़ते हुए पति-पत्नी से की और कहा कि इस राजनीतिक लड़ाई का असर राज्य के विकास पर पड़ रहा है। 1 निधि आवंटन को लेकर बढ़ी नाराजगी नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट से जुड़ी विकास कार्यों की निधि संबंधी फाइलें रोकी जा रही हैं। निधि आवंटन को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच नाराजगी बढ़ रही है। दोनों दलों के नेता एक-दूसरे के विरोध में खड़े हो रहे हैं और उनके बीच बातचीत भी कम हो गई है। 2 फडणवीस ने मजबूत की राजनीतिक स्थिति सरकार गिरने की चर्चाओं पर वडेट्टीवार ने दावा किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर ली है। सहयोगी दलों के कुछ नेता भी उनके संपर्क में हैं। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद आगामी राजनीतिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

FDA की बड़ी कार्रवाई, 5.01 करोड़

में अलग से 18.95 करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया है। एफडीए की सबसे बड़ी कार्रवाई नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में हुई, जहां 4.12 करोड़ रुपये का एक्सपायरी सामान बरामद हुआ, जो कुल जब्ती का करीब 82 प्रतिशत है। इसके अलावा, भिवंडी की सात जगहों से 73.31 लाख रुपये का माल पकड़ा गया। इस मामले में अब तक 34 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 7 कारवाई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। लगेगा 10 लाख तक का जुर्माना एफडीए ने सख्त निर्देश जारी किए है। अब गोदामों में एक्सपायरी माल के लिए अलग बंद कमरा, सीसीटीवी की निगरानी और माल नष्ट करने की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। माल हटाने से सात दिन पहले सूचना देनी होगी, गलत जानकारी देने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। खाने के तेल में मिलावट, अब एफडीए कसेगी नकेल एफडीए अधिकारियों की ओर से चलाई गई एक अलग मुहिम के तहत, 1 अप्रैल से 29 अक्टूबर 2026 के बीच राज्यभर में खाद्य तेल के 1,660 नमूने लिए गए। इस दौरान 28,753 क्विंटल तेल जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 18.95 करोड़ रुपये है। सबसे ज्यादा मात्रा में तेल पुणे विभाग में पकड़ा गया। यहां से 19,551 क्विंटल मिलावटी तेल जब्त किया गया है, जबकि कीमत के मामले में छत्रपति संभाजीनगर सबसे आगे रहा, जहां 8.34 करोड़ रुपये का तेल जब्त किया गया है। एफडीए के मुताबिक, मिलावट, गंदगी और बिना लेबल के तेल बेचने के आरोप में कुल 80 लाइसेंस निलंबित किए गए है, जिनमें अकेले संभाजीनगर के 27 लाइसेंस शामिल हैं।

पृष्ठ 1/8 का शेष

मुंबई की BDD चाल पुनर्विकास

पर मकान देने की मांग की। इस पर विचार के बाद मुंबई म्हाडा की तीनों बीडीडी परियोजनाओं में पुनर्विकास के पश्चात शेष 538 मकान गृह विभाग को मिलने की जानकारी सामने आई, जिसके आधार पर आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई। 500 वर्ग फुट के मकान देने का फैसला गृह विभाग ने 14 अक्टूबर 2024 के शासन पत्र के माध्यम से 1 जनवरी 2011 के बाद से बीडीडी चालों के सरकारी आवासों में रहने वाले और पहले अपात्र घोषित किए गए पुलिसकर्मियों को भी निर्माण लागत लेकर 500 वर्ग फुट के मकान मालिकाना हक पर देने की मंजूरी दी थी। इसके बाद मुंबई पुलिस आयुक्त ने पात्र पुलिसकर्मियों की सूची म्हाडा को सौंपी। इस सूची में वरली के 123, नायगांव के 84 और एनएम जोशी मार्ग के 16 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस तरह कुल 223 पुलिसकर्मियों को पात्र घोषित किया गया है। इनके अलावा शेष 315 सरकारी आवास पुलिस विभाग के कब्जे में होने की जानकारी पुलिस आयुक्त ने दी थी। 500 वर्ग फुट के मकान देने का फैसला गृह विभाग ने 14 अक्टूबर 2024 के शासन पत्र के माध्यम से 1 जनवरी 2011 के बाद से बीडीडी चालों के सरकारी आवासों में रहने वाले और पहले अपात्र घोषित किए गए पुलिसकर्मियों को भी निर्माण लागत लेकर 500 वर्ग फुट के मकान मालिकाना हक पर देने की मंजूरी दी थी। इसके बाद मुंबई पुलिस आयुक्त ने पात्र पुलिसकर्मियों की सूची म्हाडा को सौंपी। इस सूची में वरली के 123, नायगांव के 84 और एनएम जोशी मार्ग के 16 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस तरह कुल 223 पुलिसकर्मियों को पात्र घोषित किया गया है। इनके अलावा शेष 315 सरकारी आवास पुलिस विभाग के कब्जे में होने की जानकारी पुलिस आयुक्त ने दी थी।

बांद्रा पूर्व गरीबनगर में रेलवे

नहीं हटाया गया था, क्योंकि यहां रहने वाले पात्र परिवारों का पुनर्वास बाकी था। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने सभी पात्र परिवारों को वैकल्पिक स्थायी मकान उपलब्ध कराकर उनका कब्जा भी सौंप दिया है। पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेलवे ने जमीन खाली करा ली। इससे बांद्रा टर्मिनस के पूर्वी हिस्से में रेल सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई मुंबई उच्च न्यायालय के 23 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार रेलवे ने यह कार्रवाई की। न्यायालय ने पात्र प्रभावित परिवारों को एक सप्ताह के भीतर जगह खाली करने का निर्देश दिया था। इसके बाद रेलवे प्रशासन को 48 घंटे के भीतर संबंधित निर्माण हटाने को कहा गया था। इससे पहले मई 2026 में पश्चिम रेलवे ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। हालांकि, पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण 94 निर्माणों को उस समय नहीं हटाया गया था। आठवें प्लेटफॉर्म का होगा निर्माण जमीन खाली होने के बाद बांद्रा टर्मिनस के पूर्वी हिस्से में आठवें प्लेटफॉर्म के निर्माण का रास्ता खुल गया है। इसके साथ ही ट्रेनों को खड़ा करने के लिए अतिरिक्त जगह विकसित की जाएगी। ट्रेनों की मरम्मत और रखरखाव से जुड़ी सुविधाओं का भी विस्तार होगा। कुछ मौजूदा सुविधाओं को दूसरी जगह स्थानांतरित कर उनके लिए अधिक जगह उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं टर्मिनस पर यात्रियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए अलग से जगह, प्रतीक्षा क्षेत्र और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। ट्रेनों को खड़ा करने और उनकी मरम्मत की क्षमता बढ़ने से रेल परिचालन भी अधिक सुचारू हो सकेगा। पश्चिम रेलवे की योजना बांद्रा टर्मिनस को उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए एकीकृत रेल परिसर के रूप में विकसित करने की है। खाली कराई गई जमीन पर बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। इससे भविष्य में अधिक यात्रियों को संभालने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

फिर एक होंगी दोनों शिवसेना?

करने का रास्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी जिले के पालकमंत्री हैं, उन्हें खुद पहल करके आगे आना चाहिए और इन स्थानीय विवादों को तुरंत सुलझाना चाहिए। गठबंधन पर रुख और वरिष्ठ नेताओं को चेतावनी गठबंधन की मौजूदा स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए हेमंत पाटिल ने कहा कि फिलहाल महायुति गठबंधन में कोई बड़ी दरार या खटास नहीं पड़ी है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में यह भी जोड़ा कि वरिष्ठ नेताओं को इस स्थिति पर समय रहते ध्यान देने की सख्त जरूरत निर्माण हो चुकी है। हेमंत पाटिल के इस बयान ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भविष्य में शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच फिर से कोई तालमेल संभव हो पाएगा? हालांकि अंतिम फैसला एकनाथ शिंदे के हाथ में है, लेकिन पाटिल के इस बयान ने महाराष्ट्र के सियासी पारे को अचानक बढ़ा दिया है।

घर बैठे ट्रेन से भेजें पार्सल!

की मदद लेगा। ग्राहक रेल पार्सल ऐप या रेलवे की वेबसाइट के जरिए घर बैठे ही पिकअप का समय और स्थान बुक कर सकेंगे। उपभोक्ता ट्रेन के प्रस्थान समय से 15 दिन पहले तक या कम से कम 1 दिन पहले पार्सल बुक कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स पार्टनर ग्राहक के घर से पार्सल उठाएगा और ट्रेन रवाना होने से कम से कम 1 घंटे पहले उसे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों को सौंप देगा। दो शहरों के बीच रेलगाड़ी के जरिए पार्सल का सुरक्षित परिवहन रेलवे खुद संभालेगा, जबकि गंतव्य शहर में डोरस्टेप डिलीवरी फिर से लॉजिस्टिक्स पार्टनर द्वारा की जाएगी। लाइव ट्रैकिंग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस सेवा में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक का पूरा उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक बुकिंग पर ग्राहक को 10-अंकों का यूनिक प्रोग्रेसिव रेफरेंस रिकॉर्ड (PRR) नंबर मिलेगा, जिससे वे ऐप पर अपने पार्सल की लाइव लोकेशन आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। डिलीवरी के समय सुरक्षा और सही व्यक्ति तक पार्सल पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए OTP प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। ग्राहक UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे और उन्हें डिजिटल जीएसटी इनवॉइस प्राप्त होगा। बुकिंग कैंसिल करने और रिफंड के नियम यदि कोई ग्राहक पार्सल पिकअप होने से पहले अपनी रेल फ्रेट बुकिंग रद्द करता है, तो 10 के क्लर्केज शुल्क की मामूली कटौती के बाद रेलवे फ्रेट का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा।

भिवंडी में 57.96 लाख रुपये का प्रतिबंधित गुटखा जब्त, उत्तर प्रदेश का एक आरोपी गिरफ्तार

काल्हेर के अरिहंत कंपाउंड में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई; टेम्पो से कमला पसंद और राजश्री पान मसाला बरामद

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर और भिवंडी तालुका में प्रस्तावित अति उच्चदाब बिजली पारेषण परियोजनाओं से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से की है। इस संबंध में गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद) के युवा नेता सुमित म्हात्रे ने सांसद सुप्रिया सुले और प्रभावित किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राजस्व मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बैठक में भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के किसानों की जमीन अधिग्रहण के दौरान उचित मुआवजा, समान दर निर्धारण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास सहित विभिन्न मुद्दे उठाए गए।विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर के लिए बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी है। सांसद बाल्या मामा ने मुआवजा तय करने के लिए अलग से नई



दर निर्धारण समिति गठित करने और उसमें प्रभावित किसानों अथवा उनके प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की। साथ ही अधिग्रहित जमीनों के लिए समान रूप से दो का गुणांक लागू कर गांववार न्यायसंगत दरें निर्धारित करने तथा किसानों का उचित मुआवजा देकर पुनर्वास करने की मांग भी की गई। खावड़ा-4सी पावर ट्रांसमिशन परियोजना के तहत भिवंडी तालुका के 20 गांवों से अति उच्चदाब बिजली की लाइनें गुजरने वाली हैं। इससे किसानों की जमीन प्रभावित होगी और बिजली लाइनों के नीचे आने वाली जमीनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगेगा। सांसद बाल्या मामा ने मांग की कि किसानों को केवल बिजली के टावरों के लिए अधिग्रहित जमीन का ही नहीं, बल्कि बिजली लाइनों के नीचे प्रभावित होने वाली जमीन का भी उचित मुआवजा दिया जाए। युवा नेता सुमित म्हात्रे ने बताया कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इन मांगों पर चर्चा के लिए विशेष बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर प्रभावित किसानों को उचित न्याय दिलाने के लिए सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया गया है।

बांद्रा पूर्व गरीबनगर में रेलवे की बड़ी कार्रवाई, 94 झुग्गियां हटाई गईं, 8वें प्लेटफॉर्म का रास्ता साफ



बांद्रा पूर्व गरीबनगर में रेलवे की जमीन से बची हुई 94 झुग्गियां हटाई गईं। हाईकोर्ट के आदेश और MMRDA पुनर्वास के बाद बांद्रा टर्मिनस पर 8वें प्लेटफॉर्म का रास्ता साफ। बांद्रा पूर्व में रेलवे ने 94 झुग्गियां हटाकर जमीन खाली कराई। पात्र परिवारों को म्हाडा नहीं, एमएमआरडीए ने स्थायी मकान दिए। खाली जमीन पर आठवां प्लेटफॉर्म और यात्री सुविधाएं विकसित होंगी। बांद्रा पूर्व स्थित गरीबनगर इलाके में रेलवे की जमीन पर बनी बची हुई 94 झुग्गियों को पश्चिम रेलवे ने शुक्रवार को हटाने की कार्रवाई की। दोपहर तक सभी निर्माण तोड़ दिए गए। इन झुग्गियों को अब तक इसलिए ...शेष 7 पर

मुंबई की BDD चाल पुनर्विकास, 223 पुलिसकर्मियों को निर्माण लागत पर मिलेंगे 500 वर्ग फुट के मकान

मुंबई की बीडीडी चालों के पुनर्विकास में 223 पुलिसकर्मियों व उनके वारिसों को मालिकाना हक पर 500 वर्ग फुट के मकान मिलेंगे। गृह विभाग ने स्थानवार निर्माण लागत का GR जारी किया। बीडीडी चालों में 223 पुलिसकर्मियों और वारिसों को मालिकाना हक पर घर मिलेंगे। वरली, नायगांव और एनएम जोशी मार्ग में 500 वर्ग फुट के मकान दिए जाएंगे। शेष 315 मकान मुंबई पुलिस आयुक्त के कब्जे में रहेंगे। मुंबई की वरली, नायगांव और एनएम जोशी मार्ग स्थित बीडीडी चालों के पुनर्विकास में पुलिस विभाग के सरकारी आवासों में रहने वाले 223 पुलिसकर्मियों और उनके वारिसों को अब मालिकाना हक पर घर मिल सकेंगे। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2011 के बाद से इन आवासों



में रहने वाले पात्र पुलिसकर्मियों को 500 वर्ग फुट के पुनर्वास मकान देने का निर्णय लिया है। हालांकि, इसके लिए उन्हें निर्धारित निर्माण लागत चुकानी होगी। गृह विभाग द्वारा जारी जीआर में तीनों स्थानों के लिए अलग-अलग निर्माण लागत तय की है। वहीं, शेष 315 पुनर्वास मकान मुंबई पुलिस आयुक्त के कब्जे में देने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग के जीआर के अनुसार वरली में पुनर्वास मकान के लिए 1.48 करोड़ रुपए, नायगांव में 72.25 लाख रुपए और एनएम जोशी मार्ग पर 86.30 लाख रुपए निर्माण लागत निर्धारित की गई है। यह राशि 500 वर्ग फुट के प्रत्येक पुनर्वास मकान के लिए तय की गई है। पात्र पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों अथवा उनके वारिसों को यह रकम चुकाने के बाद मकान मालिकाना हक पर दिए जाएंगे। पहले 2011 तक के कर्मियों को मिली थी मंजूरी बीडीडी चालों के पुनर्विकास के तहत पुलिस विभाग के सरकारी आवासों का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। 18 अगस्त 2021 के शासन निर्णय के अनुसार 1 जनवरी 2011 तक आवासों में रहने वाले पुलिसकर्मियों और उनके वारिसों को पुनर्विकसित मकान मालिकाना हक पर देने की मंजूरी दी गई थी। इसके लिए प्रति मकान 15 लाख रुपए निर्माण खर्च तय किया गया था। बाद में 1 जनवरी 2011 के बाद से रह रहे पुलिसकर्मियों ने भी मालिकाना हक ...शेष 7 पर

घर बैठे ट्रेन से भेजें पार्सल! रेलवे की डोर-टू-डोर डिलीवरी सेवा, मुंबई-पुणे समेत 8 शहरों से होगी शुरुआत

रेलवे शुरू कर रहा है घर से पार्सल भेजने और पाने की डोर-टू-डोर सेवा। अब पुणे, मुंबई समेत देश के 8 शहरों के लोग ऐप या वेबसाइट के जरिए आसानी से पार्सल बुक कर सकेंगे। रेलवे द्वारा देश के आठ प्रमुख शहरों में डोर-टू-डोर पार्सल सेवा शुरू की जा रही है। अब यात्री घर बैठे ही मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए पार्सल बुक कर सकेंगे। नई सुविधा से लोगों को भारी सामान भेजने के लिए रेलवे स्टेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आईटी हब, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और देश भर से आए लाखों छात्रों की पसंदीदा नगरी मुंबई और पुणे के निवासियों के लिए एक बेहद राहतभरी और बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने एक सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद देश के 8 प्रमुख शहरों में घर से ही पार्सल बुक करने



और डिलीवरी पाने की अनूठी डोर-टू-डोर पार्सल सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इस नई पहल के शुरू होने से अब भारी-भरकम सामान या पार्सल भेजने के लिए रेलवे स्टेशन के चक्कर काटने और पार्सल कार्यालयों की लंबी लाइनों में खड़े रहने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। पुणे पर क्या होगा असर और किसे मिलेगा सीधा फायदा? महाराष्ट्र के प्रमुख आर्थिक, व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र मुंबई और पुणे में हर रोज हजारों की संख्या में छोटे कारोबारी, आईटी प्रोफेशनल्स, ई-कॉमर्स विक्रेता और विद्यार्थी एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजते हैं। घर से घर तक नाम की इस विशेष सुविधा से पुणे के लोगों को उनके घर या दुकान के दरवाजे से ही पिकअप और डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल उनका समय और पैसा बचेगा, बल्कि पार्सल बुकिंग की पूरी प्रक्रिया भी काफी सरल और पारदर्शी हो जाएगी। देश के 8 प्रमुख शहरों में शुरू हो रही है यह सेवा भारतीय रेलवे प्रथम चरण में इस अत्याधुनिक सुविधा को देश के आठ बड़े महानगरों में एक साथ शुरू कर रहा है। पुणे (महाराष्ट्र) मुंबई (महाराष्ट्र) दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) कोलकाता (पश्चिम बंगाल) चेन्नई (तमिलनाडु) अहमदाबाद (गुजरात) हैदराबाद (तेलंगाना) बेंगलुरु (कर्नाटक) कैसे काम करेगी रेलवे की यह डोर-टू-डोर प्रणाली? भारतीय रेलवे इस सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए निजी लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स ...शेष 7 पर

भिवंडी में एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री का आरोप, पांच लोगों पर मामला दर्ज

एवेन्यू सुपरमार्ट के वितरण केंद्र से 28 हजार रुपये से अधिक का माल जब्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की शिकायत पर कार्रवाई

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडी के माणकोली इलाके में एक्सपायरी और खराब खाद्य पदार्थों को कथित तौर पर बिक्री के लिए रखने के मामले में नारपोली पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की अधिकारी कस्तूरी योगेश चिपलूनकर की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, माणकोली नाका स्थित एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के वितरण केंद्र और अंजुर गांव के महावीर कॉम्प्लेक्स स्थित गोदाम में जांच के दौरान एक्सपायरी, खराब और पैकेजिंग से क्षतिग्रस्त खाद्य पदार्थ पाए गए। इनकी कुल कीमत 28,504 रुपये बताई गई है। जब्त सामान में विभिन्न कंपनियों के खाद्य तेल शामिल हैं।इस मामले में वितरण केंद्र के मैनेजर विद्याधर अनंत शिंतरे, एरिया मैनेजर अरुण भीमराव गोइलकर, कंपनी के नॉमिनी रामचंद्र राऊल, हरियाणा की केएनपी एरायसेस ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड तथा कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एल्विन एलियस मचाडो को आरोपी बनाया गया है।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने कथित रूप से आपसी मिलीभगत कर एक्सपायरी और खराब खाद्य पदार्थों को उचित तरीके से नष्ट करने के बजाय बिक्री के लिए उपलब्ध कराया। इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरा पहुंचने की आशंका थी। नारपोली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह दैनिक मालक-मुद्रक-प्रकाशक, संपादक मोहम्मद शकील अब्दुल रफीक ने सिटी इन्टरप्राजेस धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे से प्रकाशित किया, मुख्य कार्या लय- धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे महाराष्ट्र।मुंबई कार्या लय- शॉप नं. 14 उपाध्याय इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहिसर चेक नाका, मुंबई इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधीन होगा संपादक मो. शकील अ. रफीक : मो. 9869128483
Email : shakeelsahara@gmail.com / citynewsmumbai@gmail.com website : www.citynewsmumbai.in RNI No. : MAHHIN/2012/47486